पूर्ण पीठ

समक्ष एस. एस. संधवालिया मुख्य न्यायाधीश, पी. सी. जैन और एस. एस. कांग न्यायमूर्ति;

हरियाणा राज्य-अपीलार्थी।

बनाम

मान सिंह और दूसरा,-उत्तरदाता।

1977 का पत्र पेटेंट अपील संख्या **200**।

29 मार्च**, 1979**।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम ***(1894*** का ***1)-***धारा ***18-***न्यायालय जिसे धारा ***18*** के अधीन निर्देश दिया गया है ***-***क्या इसके पीछे जा सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि क्या इसे ठीक से बनाया गया था।

अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही कलेक्टर द्वारा कोई निर्देश गलत तरीके से दिया गया हो, फिर भी न्यायालय को निर्देश की वैधता का निर्धारण करना होगा क्योंकि निर्देश का ढेर लगाने के लिए न्यायालय की अधिकारिता भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* की धारा *18* के तहत किए जा रहे उचित निर्देश पर निर्भर करती है और यदि निर्देश उचित नहीं है, तो निर्देश को जमा करने के लिए न्यायालय में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह इस प्रकार है कि यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि धारा *18* में निर्धारित वैधानिक शर्तों का अनुपालन किया गया है और यह स्वयं को संतुष्ट करने से वंचित नहीं है कि जिस संदर्भ पर उसे सुनवाई के लिए बुलाया गया है वह एक वैध संदर्भ है। यह केवल एक वैध संदर्भ है जो न्यायालय को अधिकारिता देता है और इसलिए, न्यायालय को स्वयं से यह प्रश्न पूछना पड़ता है कि क्या उसके पास संदर्भ को स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र है।

*(*पैरा *4)*

माननीय न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी द्वारा दिनांक *2* मई, *1977* को दिए गए निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड *10* के अधीन लेटर्स पेटेंट अपील। *1968* का *451,* श्री वी. पी. अग्रवाल, अपर जिला न्यायाधीश, गुड़गांव दिनांक *5* अगस्त, *1968* की पुष्टि करते हुए, चाहे, चकनोत, मगड़ा, नर्मत भूमि का बाजार मूल्य *1,200/-* रुपये प्रति एकड़ और बंजर का और। गैर मुम्किन भूमि *900/-* रुपये प्रति एकड़ की दर से और यह आदेश देते हुए कि आवेदक बढ़ी हुई राशि पर *15* प्रतिशत की दर से अनिवार्य अधिग्रहण शुल्क के हकदार होंगे और वे कब्जा लेने की तारीख से भुगतान करने की तारीख तक बढ़ी हुई राशि पर *40* प्रतिशत ब्याज के भी हकदार होंगे।

ए. एस. नेहरा, अतिरिक्त अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता हनवंत सिंह हुड्डा के साथ ए. जी. हरियाणा।

कोई नहीं, प्रत्यर्थी के लिए।

हरियाणा राज्य बनाम मान सिंह और एक अन्य (एस. एस. संधवालिया, न्यायमूर्ति

निर्णय

एस. एस. संधवालिया मुख्य न्यायाधीश:-

(1) पूर्ववर्ती के एक कथित संघर्ष ने पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए इस लेटर्स पेटेंट अपील को स्वीकार करना आवश्यक बना दिया था। तथापि, अब यह अपीलार्थी-हरियाणा राज्य का निर्विवाद रुख है कि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय और अंतिम न्यायालय द्वारा इसके अनुमोदन दोनों द्वारा मामला उनके पक्ष में समाप्त हो जाता है।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तथ्यों का संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त है। अधिग्रहण की कार्यवाही में कलेक्टर द्वारा उन्हें दिए गए मुआवजे से व्यथित प्रत्यर्थी-भूमि मालिकों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदनों को प्राथमिकता दी, जिसमें मुआवजे में वृद्धि के लिए न्यायालय को निर्देश देने की मांग की गई थी। सरकार को नोटिस देने के बाद, न्यायालय को विधिवत संदर्भ दिए गए। तथापि, अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष, अपीलार्थी-राज्य की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति जोरदार ढंग से उठाई गई थी कि ये निर्देश अक्षम थे क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 द्वारा विहित शर्तें पूरी नहीं की गई थीं। लिया गया विशिष्ट आधार यह था कि संदर्भों की मांग सीमा की निर्धारित अवधि के बाद की गई थी और दावेदारों को बिना विरोध के मुआवजे को स्वीकार करने के बाद अदालत में संदर्भ की मांग करने का अधिकार नहीं था। प्रारंभिक आपत्ति को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था और उनके द्वारा मुआवजा बढ़ाया गया था।

3. हरियाणा राज्य ने तब उक्त फैसले के खिलाफ नियमित रूप से पहली अपील को प्राथमिकता दी। इसमें केवल एक ही प्रश्न उठाया गया था कि संदर्भ विशिष्ट कारणों से अक्षम थे जिनका विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष आग्रह किया गया था। विद्वत एकल न्यायाधीश ने देखा कि निर्णय के लिए एकमात्र मुद्दा यह था कि क्या यह उस न्यायालय के लिए खुला था जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ दिया गया है और यह जांच करने के लिए कि क्या यह ठीक से किया गया था। हरि किशन खोसला बनाम पेप्सू राज्य, (1) (जिसके द्वारा उन्होंने खुद को बाध्य ठहराया) में इस न्यायालय के खंड पीठ के फैसले सहित कई अधिकारियों के सिद्धांत और अनुसरण दोनों पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं थी। कलेक्टर द्वारा धारा 18 के अधीन इसका निर्देश दिया गया और सभी अपीलों को खारिज कर दिया गया।

4. सेवा के बावजूद, उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थिति नहीं दी गई है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वत अपर महाधिवक्ता श्री नेहरा ने ठीक ही तर्क दिया है कि विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षकारों के वकील ने मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, (2), जिसमें हरि किशन खोसला के मामले (उपर्युक्त) को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले को उनके संज्ञान में नहीं लाने में घोर लापरवाही बरती थी। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि विवाद अब मोहम्मद हस्नुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य (3) में उनके लॉर्डशिप के हालिया फैसले से शांत हो गया है, जिसमें इसे इस प्रकार देखा गया हैः -

"भले ही कलेक्टर द्वारा कोई संदर्भ गलत तरीके से दिया गया हो, फिर भी न्यायालय को संदर्भ की वैधता निर्धारित करनी होगी क्योंकि संदर्भ की सुनवाई करने के लिए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र धारा 18 के तहत किए जा रहे उचित संदर्भ पर निर्भर करता है, और यदि संदर्भ उचित नहीं है, तो संदर्भ को सुनने के लिए न्यायालय में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह इस प्रकार है कि यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि धारा 18 में निर्धारित वैधानिक शर्तों का अनुपालन किया गया है, और यह स्वयं को संतुष्ट करने से वंचित नहीं है कि जिस संदर्भ पर उसे सुनवाई के लिए बुलाया गया है वह एक वैध संदर्भ है। यह केवल एक वैध संदर्भ है जो न्यायालय को अधिकारिता देता है और इसलिए, न्यायालय को स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा कि क्या उसके पास संदर्भ को स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र है।

समान रूप से यह स्पष्ट नोटिस की मांग करता है कि उपरोक्त मामले में उनके लॉर्डशिप्स ने मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले (उपर्युक्त) में पूर्ण पीठ के फैसले को स्पष्ट रूप से मंजूरी दे दी है और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इसके विपरीत निर्णय अच्छे कानून को निर्धारित नहीं करते हैं और शर्तों में खारिज कर दिए गए हैं। हमारे समक्ष यह विवादित नहीं किया गया है कि वर्तमान मामले में, संदर्भों का दावा निर्धारित अवधि से परे किया गया था और आगे यह कि प्रतिवादी-भूमि मालिकों को बिना विरोध के मुआवजा स्वीकार करने के कारण उन्हें प्रस्तुत करने से रोक दिया गया था। ऐसा होने पर, इस अपील को अनिवार्य रूप से अनुमति दी जानी चाहिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रत्यर्थी-भूमि मालिकों द्वारा दिए गए संदर्भों को खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा